नईदुनिया

संपादकीय

अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप

अपनी दूसरी पारी के लिये डोनाल्ड ट्रंप फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हालांकि, अमेरिका फर्स्ट को प्राथमिकता देने वाले ट्रंप की नीतियां व्यापार व आव्रजन के मुद्दे पर भारत के लिये परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। वर्ष 2017 से 2021 के बीच राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली पारी के दौरान कई मोर्चों पर निबटने का अनुभव जरूर मोदी सरकार के पास है। गाहे-बगाहे मोदी ट्रंप को अपने दोस्त के रूप में संबोधित करते रहे हैं। हालांकि, यह कहना जल्दबाजी होगी कि हाल के दिनों में भारत के खिलाफ तल्ख रवैया अपनाने वाले बाइडन प्रशासन की नीतियों में ट्रंप आमूल-चूल परिवर्तन कर देंगे। सारी दुनिया जानती है कि अमेरिकी नीतियां अमेरिका पर शुरू होकर अमेरिका पर भी खत्म हो जाती हैं। अपने चुनाव अभियान में भी ट्रंप भारत की आर्थिक संरक्षण की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीतियों के पैरोकार ट्रंप विगत में अमेरिका से आयात होने वाली हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर टैरिफ घटाने को लेकर भारत के प्रति नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। मूल रूप से व्यवसायी से राजनेता बने ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान भी अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने को अपनी प्राथमिकता बनाया था। ऐसे में संभव है कि वे अमेरिकी उत्पादों व सेवाओं के संरक्षण को लेकर भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाएं। वे अपने कई उत्पादों पर अपनी सुविधा के अनुरूप टैरिफ बढ़ाने के लिये भारत पर दबाव बना सकते हैं। साथ ही आशंका है कि वे भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ाकर हमारे लिये आर्थिक मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जिससे भारत द्वारा अमेरिका से किया जाने वाला आयात भी महंगा हो सकता है। फलतः भारतीय उपभोक्ताओं की मुश्किलें महंगाई वृद्धि से बढ़ सकती हैं। बहरहाल, ट्रंप की सफलता से अमेरिकी कारोबार जगत खासा उत्साहित है, जिसके चलते अमेरिकी शेयर बाजार खुशी से झूमा है। लेकिन इसके बावजूद हिंद प्रशांत में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूती देगी। बहरहाल, यह एक हकीकत है कि ट्रंप एक बार फिर सत्ता में लौटे हैं और भारत तथा दुनिया को इस अप्रत्याशित चरित्र से निपटने के लिये तैयार रहना होगा। यह व्यक्ति एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताता है, वहीं भारत को अमेरिका के व्यापारिक हितों के विरुद्ध नीतियां बनाने वाला बताता है। यहां तक कि अपने चुनाव अभियान के दौरान भी ट्रंप अमेरिकी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के लिये भारत की आलोचना कर चुके हैं। साथ ही अमेरिका को फिर से असाधारण रूप से संपन्न बनाने के लिये द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में 'जैसे को तैसा' की नीति अपनाने का आह्वान किया था। ऐसे में आशंका जतायी जा रही है कि रिपब्लिकन प्रशासन अमेरिका को भारत से होने वाले 75 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात पर अधिक टैरिफ लगा सकता है। बहुत संभव है कि मोदी के मेक इन इंडिया अभियान तथा ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नजरिये के साथ टकराव पैदा हो। अपने पहले कार्यकाल में एच-1बी वीजा में कटौती के प्रयास करने वाले ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में रोजगार आधारित आव्रजन पर प्रतिकूल असर हो सकता है। कूटनीतिक मोर्चे पर नई दिल्ली को उम्मीद होगी कि ट्रंप के साथ मोदी के बेहतर तालमेल के चलते गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में मतभेद सुलझाने में मदद मिले। वैसे भी ट्रंप अमेरिकी न्याय विभाग और एफबीआई पर अविश्वास जताते हुए उन पर पक्षपाती होने के आरोप लगाते रहे हैं। उनका यह दृष्टिकोण इस जटिल मामले में भारत को राहत दे सकता है। वैसे ट्रंप से कुछ भी अप्रत्याशित करने की उम्मीद बनाये रखनी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि सामरिक मुद्दों, हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैन्य अभ्यास व तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन के साथ भारत का बेहतर तालमेल संभव है। पिछली पारी में राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप सरकार ने भारत के साथ बड़े रक्षा समझौते भी किए थे। जो फिर होने पर पाक व चीन के मुकाबले भारत को मजबूती दे सकते हैं।

राष्ट्र के सुरक्षित डिजिटल भविष्य की दिशा में कदम

ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया

तकनीकी प्रगति के साथ पैदा होने वाले खतरों से नागरिकों को बचाने के लिए एक सुदृढ़ साइबर व्यवस्था से लैस भारत का निर्माण करना होगा। भारत में, दूरसंचार की उपयोगिता लोगों को जोड़ने से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण उपकरण भी है, जो विकास के हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान का काम करता है। पिछले एक दशक में, देश में डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारी विकास हुआ है। दुनिया में सबसे सस्ते डेटा दरों के साथ, भारत में अब 954.40 मिलियन से अधिक इंटरनेट ग्राहक हैं। इनमें से 398.35 मिलियन इंटरनेट ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। पिछले एक दशक में, ब्रॉडबैंड कनेक्शन 64 मिलियन से बढ़कर 924 मिलियन हो गए हैं। इस व्यापक कनेक्टिविटी ने एक डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, जो आज हमारे कुल आर्थिक परिदृश्य में 10 प्रतिशत का योगदान देता है। वर्ष 2026 तक इस योगदान के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पांचवें हिस्से या 20 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है। बैंकिंग सेवाएं, केवाईसी सत्यापन, डिजिटल भुगतान और मोबाइल-आधारित प्रमाणीकरण भारत की डिजिटल क्रांति की रीढ़ रहे हैं, जिससे जन धन, आधार, मोबाइल (जेएएम) की तिहरी सेवाओं को फलने-फूलने में मदद मिली है। अकेले अक्टूबर 2024 में, देश में आधार समर्थ भुगतान प्रणाली के माध्यम से 126 मिलियन डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए।

हालांकि, यह डिजिटल क्रांति विकट चुनौतियां भी प्रस्तुत कर रही है। विशेष रूप से, तकनीकी प्रगति के साथ पैदा होने वाले खतरों से हमारे नागरिकों की सुरक्षा की चुनौती। हमारे हाथ में रखे जाने वाले सुविधा के ये उपकरण स्पैम कॉल, घोटाले वाले संदेश, टेलीमार्केटिंग के अनुचित कॉल, फ़िशिंग घोटाले, नकली निवेश एवं ऋण के अवसरों जैसे साइबर अपराधों के जाल से भी घिरे हैं। एक विशेष चुनौती सामने आई है: डिजिटल अरेस्ट के घोटाले आज चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं। इसकी कार्यप्रणाली के तहत - अपराधी सरकारी अधिकारियों के रूप में निर्दोष व्यक्तियों को डराने और जबरन वसूली का कार्य करते हैं। महज वित्तीय नुकसान से परे, ये दुर्भावनापूर्ण कार्यप्रणालियां आजीविका को बाधित करती हैं, विश्वास को खत्म करती हैं और उस आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं जो नागरिकों में डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से शामिल होने के लिए आवश्यक है। हालांकि, इन उभरते खतरों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए हमारे अधिकारियों ने पूरी तत्परता दिखाई है। उन्होंने फर्जी तरीकों से हासिल किए गए मोबाइल कनेक्शनों को काट दिया है और 7.6 लाख शिकायतों के माध्यम से 2,400 करोड़ रूपये से अधिक की राशि की हानि को बचाया। यह महज आंकड़ों को ही नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा और सपनों की सुरक्षा को भी दर्शाता है।

अब जबकि हम डिजिटल स्पेस की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, हमारे नागरिकों के सहयोग के बिना यह एक निरर्थक कवायद साबित होगी। प्रधानमंत्री (पीएम) नरेन्द्र मोदी का हाल ही में नागरिकों से रुको, सोचो और एक्शन लो का आह्वान इंटरनेट की छाया में बढ़ते खतरों को रेखांकित करते हुए तात्कालिकता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। यह आह्वान केवल बढ़ते साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भर नहीं है, बल्कि एक सतर्क और सक्रिय समाज के निर्माण की दिशा में एक अपील भी है। कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) में किया जाने वाला चतुराई भरा यह हेरफेर इन कॉलों को वैध स्थानीय नंबर कॉल के रूप में छिपाना संभव बना देता है, जिससे धोखे का परिदृश्य और भी जटिल हो जाता है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम लॉन्च किया है। यह उपकरण एक बड़ा बचाव साबित हो रहा है, जो 86 प्रतिशत नकली कॉलों- लगभग 1.35 करोड़ कॉल प्रतिदिन - को रोक रहा है। साइबर-सुरक्षित भारत के हमारे दृष्टिकोण के केन्द्र में नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण है। 'संचार साथी' प्लेटफॉर्म इस मिशन का प्रतीक है, जिसमें चक्षु जैसे टूल हैं जो उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध संदेशों, कॉल और व्हाट्सएप गतिविधियों की रिपोर्ट करने में समर्थ बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का लाभ उठाते हुए, डीओटी ने 2.5 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शनों का पता लगाया और उन्हें काट दिया, 2.29 लाख से अधिक मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक कर दिया, 71,000 विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपीएस) के माध्यम से 1,900 अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

युवा, तकनीक-प्रेमी आबादी के लाभ के साथ, हमने विद्यार्थियों को भी जमीनी स्तर की पहल में शामिल किया है। देश भर में कॉलेज के विद्यार्थियों ने संचार मित्र स्वयंसेवकों के रूप में कदम बढ़ाया है। ये स्वयंसेवक समुदायों तक पहुंच रहे हैं और 'संचार साथी' पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ये युवा हिमायती नागरिकों को दूरसंचार धोखाधड़ी को रोकने के लिए उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करने में मदद करते हैं। मई 2023 में अपनी स्थापना के बाद से, संचार साथी पोर्टल ने 7.7 करोड़ विजिट और प्रतिदिन औसतन दो लाख उपयोगकर्ताओं के साथ जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। इस पोर्टल ने 12.59 लाख चोरी और खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस धारणा को मजबूत करते हुए कि साइबर रक्षा और सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, यह पोर्टल अपने डिजिटल अनुभवों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध नागरिकों के लिए एक आवश्यक संसाधन बन गया है। स्पैम कॉल, अनचाहे एसएमएस और टेलीमार्केटिंग के खतरे से निपटने के एक निर्णायक प्रयास के तहत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जवाबी उपायों की एक मजबूत श्रृंखला भी लागू की है। नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड लगाया जाएगा, जो डिजिटल विश्वास के उल्लंघन के प्रति शून्य-सहिष्णुता (जीरो-टोलेरेंस) की नीति का परिचायक है। अब तक, ट्राई ने असत्यापित प्रचारात्मक कॉल में संलग्न 800 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जबकि 1.8 मिलियन से अधिक नंबर काट दिए गए हैं। ऐसी सख्त कार्रवाई एसएमएस संबंधी धोखाधड़ी के मामले में भी की गई है, जिसके तहत 350,000 अप्रयुक्त और असत्यापित मैसेजिंग हेडर और 1.2 मिलियन कंटेंट टेम्पलेट को ब्लॉक कर दिया गया है। हमारी साइबर रक्षा रणनीति के केन्द्र में डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) है, जो 460 बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित 520 से अधिक हितधारकों को एकजुट करता है।

तेजी से विकसित हो रहे इस डिजिटल युग में, साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देना महज एक सावधानी भर नहीं है। बल्कि यह हमारे देश के डिजिटल भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से एक आवश्यक कदम है। एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, तकनीक-प्रेमी युवा आबादी और मजबूत संस्थागत ढांचे के साथ, भारत ने खुद को डिजिटल इकोसिस्टम में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है। जैसे-जैसे हम इस जटिल परिदृश्य में आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर सुधार और अनुकूलनशीलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ बनी रहेगी। प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप कार्य करते हुए, हम एक सुदृढ़ साइबर व्यवस्था से लैस भारत का निर्माण करेंगे - जहां प्रत्येक नागरिक सुरक्षित, सशक्त और इस डिजिटल युग में फलने-फूलने के लिए तैयार हो।

(लेखक: केन्द्रीय संचार तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री हैं।)

राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में गढ़ बचाने में लगी पार्टियां

नजरिया

रमेश सर्राफ धमोरा

राजस्थान में 13 नवंबर को सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। सात में से पांच विधानसभा सीटें झुंझुनू, दौसा, खींवसर, देवली-उनियारा, चौरासी विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं। सलूंबर व रामगढ़ में विधायकों की मृत्यु होने के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि उपचुनाव के नतीजों से प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को भी कोई खतरा होने वाला नहीं है। मगर उपचुनाव के नतीजे का असर प्रदेश की राजनीति में कई पार्टियों व उनके नेताओं के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में सात विधानसभा सीटों में से चार सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे। वहीं एक सीट पर भाजपा, एक पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) व एक पर भारतीय आदिवासी पार्टी का विधायक था।

राजस्थान की जिन सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के पास सिर्फ एक सलूंबर की सीट थी। जहां उनके लगातार तीन बार के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के चलते उपचुनाव हो रहा है। भाजपा के लिए सलूंबर की सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। भाजपा ने दिवंगत विधायक की पत्नी शांता मीणा को टिकट दिया है। इसके अलावा प्रदेश की अन्य विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। उपचुनाव में हार-जीत के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बहुत अच्छा नहीं रहा था। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि सभी सात सीटों पर भाजपा जीते,

जिससे आला कमान की नजरों में उनकी मजबूत छवि बन सके। भाजपा समय रहते अपने सभी बागियों को मना कर एकजुटता का संदेश देने में सफल रही है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भूमिका अहम है।

भाजपा ने दौसा सीट पर राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोडीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है। दौसा सीट सामान्य वर्ग की सीट है। भाजपा ने डॉक्टर किरोडीलाल मीणा के दबाव में अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। वही 2023 के विधानसभा चुनाव में झुंझुनू से भाजपा के प्रत्याशी निशित कुमार उर्फ बबलू के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र भांभू व रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सुखवंत सिंह को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। देवली-उनियारा सीट पर भी भाजपा ने पिछली बार चुनाव लड़े कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैसला का टिकट काटकर पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा है। वहीं खींवसर सीट पर रालोपा के अध्यक्ष व नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को पिछले विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देकर मात्र 2059 वोटों से हारने वाले रेवतराम डागा को फिर से मैदान में उतारा है। चौरासी सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की करारी हार हुई थी। इस बार भाजपा ने वहां नया प्रत्याशी कारीलाल ननोमा को मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी सीमलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान हैं तथा सादड़िया के सरपंच रह चुके हैं। अब उनकी पुत्रवधू रेखा सरपंच है। उनकी पत्नी हाकली देवी भी सरपंच रह चुकी है। क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने के कारण राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस बार वहां भाजपा कड़ी टक्कर दे सकती है। कांग्रेस को अपनी चार सीट झुंझुनू, दौसा, देवली-उनियारा व रामगढ़ फिर से जीतनी होगी। साथ ही अन्य तीन सीटों पर भी अपनी ताकत दिखानी होगी। कांग्रेस ने झुंझुनू सें सांसद बने बृजेंद्र सिंह ओला के बेटे अमित ओला को मैदान में उतारा है। अमित ओला ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी है तथा उनके दादा शीशराम ओला झुंझुनू से पांच बार सांसद, नौ बार विधायक केंद्र तथा राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वहीं रामगढ़ सीट पर दिवंगत विधायक जुबेर खान के पुत्र आर्यन खान को उतार कर सहानुभूति के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। दौसा सामान्य सीट पर कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के दीनदयाल बैरवा को टिकट देकर मैदान में उतारा है।

देवली-उनियारा से पूर्व अधिकारी कस्तूर चंद मीणा को मैदान में उतारा है। यहां कांग्रेस के बागी नरेश मीणा चुनाव को त्रिकोणात्मक बना रहे हैं। नरेश मीणा को कांग्रेस मनाने में नाकाम रही है, जिसके चलते कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं मानी जा रही है। सलूंबर में कांग्रेस ने 2018 में निर्दलिय चुनाव लड़कर कांग्रेस को हराने वाली रेशमा मीणा को मैदान में उतारा है। इससे नाराज होकर सांसद, विधायक व मंत्री रह चुके रघुवीर मीणा अंदर खाने पार्टी प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चौरासी सीट पर कांग्रेस ने इस बार 29 साल के नए प्रत्याशी महेश रोत को मैदान में उतारा है। खींवसर सीट पर कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी रतन चौधरी को मैदान में उतार कर हनुमान बेनीवाल के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई है। इसका फायदा भाजपा को हो सकता है। खींवसर सीट पर रालोपा के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। पिछला विधानसभा चुनाव वह मात्र 2059 वोटों से जीते थे। फिर कांग्रेस से गठबंधन कर नागौर से सांसद चुने जाने पर उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। अब उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा है। यहां उनका मुकाबला भाजपा के रेवत राम डागा व कांग्रेस की रतन चौधरी से होगा।

हनुमान बेनीवाल ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के रेवत राम डागा को महज 2059 वोटों से हराया था। विधानसभा उपचुनाव में यदि हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव हार जाती हैं तो उनकी पार्टी का विधानसभा में प्रतिनिधित्व तो समाप्त होगा ही साथ ही उनका प्रदेश की राजनीति में प्रभाव भी कम हो जाएगा। इसलिए हनुमान बेनीवाल के लिए उपचुनाव में करो व मरो वाली स्थिति बनी हुई है। आदिवासी बहुल चौरासी विधानसभा सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार रोत 69166 वोटो से चुनाव जीते थे। उनके बांसवाड़ा-डूंगरपुर से सांसद बनने के चलते इस्तीफा देने से खाली हुई चौरासी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आदिवासी बेल्ट में भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रभाव लगातार प्रभाव बढ़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के तीन विधायक जीते थे। चौरासी सीट पर कांग्रेस व भाजपा ने भी इस बार नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी का बागी बदामीलाल ताबियाड़ भी चुनाव मैदान में खड़ा है।

आजकल

124 साल बाद मौसम ने दिखाए तेवर, खतरे का तापमान

पिछले कई दशक से वैश्विक ताप में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। इसकी वजह से समूची दुनिया में गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। मगर विडंबना है कि इस मसले पर ऐसा कुछ भी ठोस नहीं किया जा रहा, जिससे तापमान संतुलन की उम्मीद जगे। उल्टे अब मौसम में उथल-पुथल इस कदर होनी शुरू हो गई है कि जिन महीनों में ठंड की आहट मिलने लगती थी, उनमें तापमान चढ़ा हुआ रहने लगा है, जो आने वाले संकट का संकेत दे रहा है।

मसलन, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, देश में इस वर्ष अक्टूबर का महीना सन 1901 के बाद सबसे अधिक गर्म रहा और औसत तापमान सामान्य से 1.23 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यानी एक सौ चौबीस वर्षों के बाद पहली बार अक्टूबर के महीने में मौसम में गर्मी इतनी थी कि उसे सामान्य नहीं माना जा रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि नवंबर में भी अगले दो सप्ताह तक तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री ऊपर बना रहेगा।

फिलहाल मौसम के उतार-चढ़ाव ने मौसम विज्ञानियों के सामने भी अध्ययन का नया फलक खोल दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ के अभाव और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात सहित कई निम्न दबाव वाले क्षेत्रों के बनने से औसत न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। हाल के दशकों में वैश्विक ताप में बढ़ोतरी के लिए जिन कारकों की पहचान की गई है, उसका हल निकालने को लेकर सक्रियता तो दिखती है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि जिन देशों को कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है, वहां इसमें कमी करने को लेकर कोई उत्सुकता नहीं दिखती।

सारी जवाबदेही विकासशील देशों पर थोप दी जाती है। हालांकि यह समस्या केवल एक या कुछ देशों तक सीमित नहीं है। समूचा विश्व इससे प्रभावित है और मौसम की इस अनियमितता को सभी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मौसम की अपनी गति होती है और उसमें समय-चक्र के मुताबिक तापमान में उतार-चढ़ाव होता रहता है, लेकिन अगर वक्त रहते इस संकट से निपटने के उपाय नहीं किए गए तो इसकी मार को झेलना मुश्किल होता जाएगा।

विरोधी नहीं, एक-दूसरे के पूरक थे नेहरू-पटेल

मुद्दा

विश्वनाथ सचदेव

हाल ही में देश ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 149वीं जयंती मनायी है। बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया है। इस संदर्भ में हुए आयोजनों में जहां एक ओर पांच सौ से अधिक देसी रियासतों को जोड़कर एक नये भारत के निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका को सराहा गया, वहीं यह बात भी कहना ज़रूरी समझा गया कि उन्हें उनका उचित देय नहीं मिला है, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बढ़ा-चढ़ा कर कुछ ज़्यादा ही बखान किया जाता है। सच्चाई तो यह है कि इन दोनों महापुरुषों ने नये भारत की नींव रखने में जो भूमिका निभायी है उसे कमतर आंकने की किसी भी कोशिश का समर्थन नहीं होना चाहिए। दोनों का योगदान अप्रतिम है। यह बात दूसरी है कि अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग ऐसी कोशिशें लगातार कर रहे हैं।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरदार की जन्म जयंती को देश एकता दिवस के रूप में मनाता है, यह भी प्रधानमंत्री की पहल पर ही हुआ है। लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि देश के दो सपूतों, नेहरू और पटेल, को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में दिखाया जाये? सवाल यह भी उठता है कि क्या सचमुच इन दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा रही थी? यह बात भी अक्सर कही जा रही है कि नेहरू की जगह यदि सरदार पटेल देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो स्वतंत्र भारत का नक्शा कुछ अलग ही होता। पटेल के प्रशंसक और नेहरू के आलोचक इस 'अलग' को अपने-अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेहरू और पटेल दोनों में कई मुद्दों पर मतभेद था। कश्मीर और हैदराबाद का प्रकरण एक ऐसा मुद्दा था। चीन के प्रति नेहरू के दृष्टिकोण से भी सरदार पटेल सहमत नहीं थे। पर इसका अर्थ एक-दूसरे का विरोधी होना नहीं है। सच्चाई तो यह है कि दोनों एक-दूसरे के प्रशंसक थे, दोनों देश का हित चाहते थे और दोनों एक-दूसरे के महत्व को स्वीकार करते थे। दोनों ने कुछ मुद्दों पर असहमति छिपाने का प्रयास कभी नहीं किया। इस असहमति को एक-दूसरे के प्रति शत्रुता के भाव के रूप में देखना या दिखाना दो महापुरुषों की बौद्धिक क्षमता पर सवालिया निशान लगाना होगा।

नेहरू और पटेल को एक-दूसरे का विरोधी निरूपित करने वाले इस बात को बार-बार दुहराते हैं कि कांग्रेस पार्टी की प्रांतीय समितियों ने एकमत से पटेल को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की इच्छा जाहिर की थी, और यह भी सही है कि तब जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनता वही स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री भी होता। सही यह भी है कि तब हस्तक्षेप करके महात्मा गांधी ने नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया था। ज्ञातव्य है कि यह काम पर्दे के पीछे से नहीं हुआ था। गांधी ने अपना पक्ष बड़ी साफगोई से सामने रखा था, और गांधी के कहने पर ही सरदार पटेल ने तब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग कर लिया था। और नेहरू के लिए स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था। यहीं इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में पटेल को शामिल करने, न करने, पर नेहरू के मन में कोई हिचक नहीं थी। तब अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नेहरू ने जो पत्र पटेल को लिखा था, उसमें उन्होंने पटेल को 'अपनी कैबिनेट का सबसे मज़बूत स्तंभ' कहा था। नेहरू पटेल की क्षमता-योग्यता से अच्छी तरह परिचित थे और मंत्रिमंडल में उनकी आवश्यकता को पूरी तरह समझते थे। नेहरू के उस पत्र के उत्तर में पटेल ने जो लिखा अब वह भी सार्वजनिक हो चुका है अपने उस पत्र में सरदार पटेल ने नेहरू को लिखा था, 'मैं जीवन भर आपको समर्थन दूंगा'। पटेल ने उस पत्र में यह भी कहा था कि 'उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आपका पूरा साथ दूंगा, जिसके लिए और किसी ने इतना त्याग नहीं किया जितना आपने किया है। हमारा साथ अटूट है, और यही हमारी ताकत है।' हमारे इतिहास का एक सच यह भी है कि जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसी दिन पटेल राष्ट्रपिता से मिले थे और नेहरू के साथ रिश्तों के बारे में उनमें लंबी बातचीत हुई थी। इस बातचीत में वे सब गिले-शिकवे धुल गये थे जो तब हवा में तैर रहे थे। उसी शाम नेहरू को भी महात्मा गांधी से मिलना था। काश! वह मीटिंग हो पाती तो बातें और साफ होकर सामने आ जातीं। पर यह नहीं हो पाया। गोडसे उन खतरनाक ताकतों के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था जिन्हें उन सपनों से नफरत थी जो गांधी, नेहरू और पटेल स्वतंत्र भारत के लिए देख रहे थे। आज पटेल और नेहरू को एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी के रूप में सामने रखकर अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति की कोशिशें हो रही हैं।